कोटद्वार, रविवार
29 मार्च 2026
वर्षः 48
अंकः 299 पृष्ठः 4
मूल्यः 2.00

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नगेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोन: 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

रणथंभौर में सफारी करने के बाद होटल पहुंची विदेशी पर्यटक की खाना खाने के बाद मौत

सवाई माधोपुर (एजेंसी)। राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर में सफारी करने के कुछ घंटे बाद एक विदेशी पर्यटक की मौत हो गई। आयरलैंड की निवासी टूरिस्ट एक ग्रुप के साथ घूमने आई थी। गुरुवार रात को होटल में अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप के बाद उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। टूरिस्ट का पोस्टमॉर्टम आयरलैंड एम्बेसी के अप्रूवल के बाद ही होगा। कुण्डेरा थाने के एएसआई ने बताया कि आयरलैंड की मरियन फांसिस (40) दोस्तों के साथ 25 मार्च को रणथंभौर आई थी। उनका ग्रुप हेरिटेज हवेली होटल में रुका था। सभी ने 26 मार्च को सुबह-शाम के स्लॉट में सफारी की थी। इसके बाद वे होटल आ गए थे। गुरुवार देर रात खाने के बाद करीब 2.30 बजे मरियन की तबीयत बिगड़ी थी। मरियन के दोस्तों ने होटल स्टाफ को सूचित किया। इसके बाद मरियन को अपेक्स सेविका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। रात करीब तीन बजे मरियन को सवाई माधोपुर के जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। इस दौरान पुलिस भी निजी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। पुलिसकर्मियों के साथ मरियन के दोस्त उन्हें सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने मरियन की जांच की। कुछ देर बाद उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने बताया कि महिला टूरिस्ट की ईसीजी कराई थी, लेकिन रिजल्ट फ्लैट था। इसके बाद उनका फिर से चेकअप किया गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम के बाद ही सामने आएगा। वहीं, पुलिस का कहना है महिला की मौत की जानकारी आयरलैंड एम्बेसी को दी गई है। अब दूतावास की परमिशन का इंतजार है।

अजित पवार हादसे के बाद डीजीसीए ने जारी की नई गाइडलाइन... फ्लाइट क्रू पर कोई दबाव ना डाला जाए

नई दिल्ली (एजेंसी)। वीआईपी और वीवीआईपी (जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि) को ले जाने वाले नॉन-शेड्यूल्ड विमान और हेलिकॉप्टर ऑपरेटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। डीजीसीए ने दो टूक कहा कि फ्लाइट क्रू पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाए, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा से समझौता न हो। डीजीसीए के मुताबिक वीआईपी की जरूरत के नाम पर आखिरी वक्त में हो रहे बदलाव सीधे क्रू से नहीं, सिर्फ ऑपरेटर्स मैनेजमेंट के द्वारा कराए जाएं। मौसम से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। क्रू के फैसले का सम्मान करना होगा। डीजीसीए की नई गाइडलाइन में ध्यान रखा गया है कि वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में पायलट थकावट का शिकार न हों। अब अगर कोई नेता दबाव डालता है, तब पायलट सीधे मना कर सकता है और इसकी जवाबदेही मैनेजमेंट की होगी, न कि व्यक्तिगत पायलट को जबावदार माना जाएगा। दरअसल, 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश में अजित पवार सहित 5 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से डीजीसीए ने वीआईपी मूवमेंट्स को लेकर नियमों में बदलाव किया है।

डिजिटल एडिक्शन से बच्चों की आत्महत्या के मामले बढ़े

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा में डिजिटल एडिक्शन का मुद्दा गंभीरता से उठाया गया, जिसमें बच्चों और युवाओं में बढ़ती मोबाइल लत पर चिंता जताई गई। चर्चा के दौरान दावा किया गया कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया के दबाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक कई बच्चे रोजाना 7 से 8 घंटे मोबाइल पर बिता रहे हैं, जिससे पढ़ाई, सामाजिक जीवन और नींद प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल लत अवसाद, चिंता और अकेलेपन की भावना को बढ़ा सकती है। कुछ मामलों में यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि बच्चे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। सदस्यों ने सरकार से इस विषय पर व्यापक चर्चा और ठोस नीति बनाने की मांग की है। साथ ही अभिभावकों को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने और मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर संवाद करने की सलाह दी गई है।

सक्रिय हो रहा वेदर सिस्टम... आज से देश के कई राज्यों में आंधी और बारिश की संभावना

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में मौसम तेजी से बदल रहा है और कई राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की संभावना जाहिर की गई है। राजस्थान में शनिवार से नया वेदर सिस्टम सक्रिय हुआ है, जिसका असर राज्य के सभी जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश के साथ ओले गिरने की भी आशंका है। बीते 24 घंटों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में मौसम साफ और धूप तेज रही, लेकिन अब बदलाव शुरू हो गया है। मध्यप्रदेश में 29 मार्च से लगातार तीन दिन तक आंधी और बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय रहेगा। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित करीब 40 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि, शनिवार को प्रदेश में गर्मी का असर बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदला हुआ है। लखनऊ और कानपुर समेत कई जिलों में रुक-रुककर बारिश हो रही है, और अगले पांच दिनों तक यही स्थिति बनी रह सकती है। कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। बिहार में पटना सहित कई जिलों में आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई, और आज 38 जिलों में अलर्ट जारी है। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का असर दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में अगले छह दिनों तक बर्फबारी की संभावना है। वहीं जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर-लेह हाईवे पर एवलांच की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। आने वाले दो दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में हल्की बारिश हो सकती है। 30 मार्च को पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश के आसार हैं।

लॉकडाउन लगेगा या नहीं शाह ने साफ कर दी सरकार की मंशा, कई अफवाहों को खारिज किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत में लॉकडाउन की चर्चाओं पर केंद्र सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया है। सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर ईंधन की कमी के तर्क के साथ लॉकडाउन लगाए जाने की अफवाहों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि देश में एलपीजी सिलेंडर या अन्य ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में आए उछाल के बावजूद भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखला और कीमतों को स्थिर बनाए रखने में पूरी तरह सफल रहा है। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि जब दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें आसमान छू रही हैं, तब भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयात के स्रोतों का विस्तार किया है। पहले

भारत अपनी ईंधन जरूरतों के लिए 27 देशों पर निर्भर था, लेकिन अब यह दायरा बढ़ाकर 42 देशों तक कर दिया गया है। गृह मंत्री ने साफ किया कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा और सामान्य कामकाज निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और नागरिकों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच टीम इंडिया की भावना से काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया कि वे राज्यों में आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करें और जमाखोरी व मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से गलत सूचनाओं और अफवाहों के प्रसार के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने जिस तरह सामूहिक शक्ति से वैश्विक बाधाओं का सामना किया था, वही समन्वय आज भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के एन चंद्र बाबू नायडू, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और पंजाब के भगवंत मान समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। यह पहली बार था जब प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी को शुरू हुए इस अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के प्रभाव को लेकर राज्यों के साथ सीधा संवाद किया।

सूरत में फर्जी पेट्रोल पंप का हुआ भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

-अमरोली इलाके में चाय की टपरी के पास चल रहा था अवैध धंधा, 800 लीटर घटिया डीजल व टैंकर जब्त

सूरत (एजेंसी)। गुजरात के सूरत में पुलिस ने अवैध रूप से संचालित एक फर्जी पेट्रोल पंप का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शहर के अमरोली इलाके में की गई, जहां चाय की एक टपरी के पास लंबे समय से सस्ते दामों पर घटिया गुणवत्ता का डीजल बेचा जा रहा था।

पुलिस के अनुसार, अमरोली-वेलंजा रोड स्थित अंजनी इंडस्ट्रीज कैनाल के पास आरोपियों ने अवैध रूप से पेट्रोल पंप जैसा सेटअप तैयार कर रखा था। यहां ग्राहकों को कम कीमत का लालच देकर खराब क्वालिटी का डीजल बेचा जाता था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और पूरे रैकेट का खुलासा किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से करीब 800 लीटर डीजल जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 61,600 रुपये बताई गई है। इसके अलावा दो टैंकर और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 22.70 लाख रुपये आंकी गई है। इस मामले में 43 वर्षीय भरत केरासिया और 32 वर्षीय महेश खिसडिया को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि इस अवैध कारोबार में दो अन्य लोग भी शामिल हैं, जो फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अमरोली पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, आरोपी लंबे समय से इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहे थे और सस्ते ईंधन के नाम पर लोगों को ठग रहे थे। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि यह डीजल कहां से लाया जा रहा था और इस नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई से इलाके में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्ती का संदेश गया है और स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है।

मुंबई में 75 लोगों ने इच्छामृत्यु के लिए दिए आवेदन, बीएमसी ने सुरक्षित रखे

-मेयर बोलीं- हमें दस्तावेजों को रखने की अनुमति, उन्हें लागू करने का अधिकार नहीं

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई में इच्छामृत्यु को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को 75 लोगों ने इच्छामृत्यु के लिए आवेदन दिए हैं। यह घटनाक्रम देश के पहले कोर्ट से मंजूर इच्छामृत्यु मामले के बाद सामने आया है, जिसने लोगों को इस दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है। इन आवेदनों में लोगों ने साफ लिखा है कि अगर वे किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाएं या किसी हादसे के बाद कोमा जैसी स्थिति में चले जाएं, जहां ठीक होने की कोई उम्मीद न हो, तो उन्हें इच्छामृत्यु का विकल्प दिया जाए। इसके लिए उन्होंने लिविंग विल भी तैयार कर नोटरी करवाई है और संबंधित अधिकारियों के पास जमा किया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की महापौर रितु तावड़े ने इस मुद्दे पर कहा कि बीएमसी इन आवेदनों को सिर्फ सुरक्षित रख रही है। उन्होंने कहा कि जो भी मरीज इच्छामृत्यु के लिए पत्र देता है, हम उसे सुरक्षित रखते हैं, लेकिन उसे लागू करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। यह जिम्मेदारी परिवार की होती है। कोर्ट ने हमें इन दस्तावेजों को रखने की अनुमति दी है, लेकिन उन्हें लागू करने का अधिकार नहीं दिया है। बता दें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद, जिसमें भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई, बीएमसी ने हर वार्ड में मेडिकल अधिकारियों को लिविंग विल पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी है। जो भी व्यक्ति लिविंग विल जमा करना चाहता है, उसे नोटरी फॉर्मेट में दस्तावेज तैयार कर अपने वार्ड ऑफिस में जमा करना होता है।

रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल बीएमसी के पास कुल 75 आवेदन आ चुके हैं। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल या ऐप तैयार करने पर काम कर रही है, ताकि लोग आसानी से आवेदन कर सकें। इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में हरीश राणा का केस भी है, जो भारत में कोर्ट से मंजूर इच्छामृत्यु पाने वाले पहले इंसान थे। 31 साल के हरीश राणा का निधन दिल्ली के एम्स में हुआ, जहां उन्हें पेलिएटिव केयर दी जा रही थी। हरीश राणा 2013 से कोमा में थे। वह उस समय इंजीनियरिंग के छात्र थे और चौथी मंजिल से गिरने के बाद उन्हें सिर की चोट लगी थी। लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद उनके माता-पिता ने जीवनरक्षक उपकरण हटाने की अनुमति मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। यह फैसला भारत के कानूनी और मेडिकल इतिहास में एक अहम मोड़ माना गया।

सीएम ममता पर आयोग की नजर, एसआई को निलंबित कर भाषण की मांगी कॉपी

बड़ी रैलिया के साथ ही डोर-टू-डोर संपर्क अभियान चलाएगी

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां और चुनावी हिंसा को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाते हुए एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित भाषण पर रिपोर्ट तलब की है, वहीं दूसरी तरफ कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिस इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राज्य में दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस भाषण पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जो उन्होंने दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी स्थित

एक जनसभा के दौरान दिया था। आरोप है कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को कथित तौर पर धमकाया। वीडियो साक्ष्यों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने महिलाओं और लड़कियों से मतदान केंद्रों पर डटे रहने को कहा और जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए घरेलू रसोई के उपकरणों का इस्तेमाल करने की बात कही। आयोग इस मामले में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के पहलुओं की जांच कर रहा है।

समानांतर कार्रवाई करते हुए, चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले के बासंती पुलिस स्टेशन के प्रभारी इंस्पेक्टर अविजित पॉल को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 26 मार्च को बासंती बाजार इलाके में हुई हिंसक घटना के बाद की गई है। आयोग के अनुसार, भाजपा उम्मीदवार विकास सरदार के चुनाव प्रचार के दौरान हुई इस हिंसा में पुलिसकर्मी और कई अन्य लोग घायल हुए थे। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पर्याप्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की उपलब्धता के बावजूद इंस्पेक्टर ने सुरक्षा की मांग नहीं की और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल रहे, जो ड्यूटी में गंभीर कोताही को दर्शाता है। इस घटनाक्रम पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। भाजपा सांसद बिप्लब कुमार देब ने इस हमले को सुनियोजित बताते हुए राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि ज्ञात हमलावरों ने पार्टी कार्यकर्ताओं और बीच-बचाव करने आए सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। देब ने राज्य में हिंसा के माहौल के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, सत्तारूढ़ दल इन आरोपों को चुनावी हथकंडा बता रहा है। फिलहाल, चुनाव आयोग की इन सख्त कार्रवाइयों ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या भड़काऊ बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

असम में चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस एक ही कम्युनिटी की पार्टी बन जाएगी : सीएम सरमा

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर सिर्फ एक समुदाय की पार्टी होने का आरोप लगाया। हिमंता ने कहा कि करीब 99 फीसदी हिंदू कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। राज्य में इसके टूटने का प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है। नतीजों के बाद कांग्रेस एक ही कम्युनिटी की पार्टी बन जाएगी। असम में 9 अप्रैल को सिंगल फेज में चुनाव हैं। 30 मार्च को पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए एक रैली को वर्चुअली संबोधित करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य बीजेपी ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से इस अनोखी और इंटरैक्टिव पहल में हिस्सा लेने के लिए ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करने की बात कही है। असम में 126 सीटों वाली विधानसभा के लिए मौजूदा बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा। सरमा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करने की कोशिश करेगी जबकि कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता में फिर वापसी का है।

शंकराचार्य पर केस करने वाले ब्रह्मचारी को पाकिस्तान से मिली धमकी कहा- बम से उड़ा देंगे

शामली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के कांधला क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट (मथुरा) के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी को जान से मारने की धमकी दी गई है। आशुतोष महाराज ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके अधिवक्ता को बम से उड़ाने की सीधी चेतावनी दी गई है। इस मामले ने तब और भी गंभीर रूप अख्तियार कर लिया जब पुलिस की प्रारंभिक जांच में वह मोबाइल नंबर पाकिस्तान का पाया गया। अंतरराष्ट्रीय नंबर से आई इस कॉल ने सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। इस पूरे विवाद की जड़ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ा एक कानूनी मामला बताया जा रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने उच्च न्यायालय द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दी गई अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और वहां एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। महाराज के अनुसार, जैसे ही उन्होंने 25 मार्च को देश की शीर्ष अदालत में इस मामले की पैरवी तेज की, उन्हें डराने-धमकाने का सिलसिला शुरू हो गया। शुक्रवार शाम लगभग 5ः53 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई, जिसमें फोन करने वाले ने स्पष्ट शब्दों

में कहा कि यदि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस नहीं ली, तो उन्हें और उनके वकील को बम से उड़ा दिया जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही कांधला थाना पुलिस और भारी बल मौके पर पहुंचा। शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सर्विलांस टीम को सक्रिय किया। जांच में पुष्टि हुई है कि जिस नंबर से धमकी भरी कॉल आई थी, उसका कंट्री कोड पाकिस्तान का है। एसपी ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस अंतरराष्ट्रीय कॉल के पीछे स्थानीय स्तर पर कौन लोग शामिल हो सकते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपकर अपनी और अपने सहयोगियों की जान को खतरा बताते हुए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे धर्म और न्याय की इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कांधला स्थित उनके आवास के आसपास सतर्कता बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियां भी इस कॉल के मूल स्रोत और किसी संभावित साजिश की जांच में जुट गई हैं।

असम में मिया वाले बयान से गरमाई सियासत, जुबानी जंग के भरोसे लड़ा जा रहा विस चुनाव

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम विधानसभा चुनाव के करीब आते ही राज्य की राजनीति में जुबानी जंग और तीखी हो गई है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के एक ताजा बयान ने राज्य के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। गुवाहाटी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अजमल ने दावा किया कि आगामी चुनाव के बाद असम की राजनीति में मिया समुदाय का दबदबा काफी बढ़ जाएगा और वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का प्रभाव कम हो जाएगा। उनका कहना है कि चुनाव परिणामों के बाद राज्य का सत्ता संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा।

असम की राजनीति में मिया शब्द का प्रयोग बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए किया जाता है। राज्य की करीब 3.12 करोड़ की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 34 प्रतिशत है, जिसमें से बड़ा हिस्सा बंगाली भाषी

मुसलमानों का है। अजमल का यह बयान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के उस पिछले विवादित बयान के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि पिछले पांच वर्षों में उनकी सरकार ने मियाओं के हाथ-पैर तोड़े हैं और अगले पांच वर्षों में उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। इन बयानों के बाद राज्य में ध्रुवीकरण की राजनीति और तेज होने की संभावना है।

इस चुनावी समर में एआईयूडीएफ को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी साथ मिल रहा है। अजमल ने जानकारी दी है कि ओवैसी 2 और 3 अप्रैल को असम के दौरे पर रहेंगे, जहां वे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम आठ जनसभाओं को संबोधित करेंगे। खुद बदरुद्दीन अजमल इस बार बिन्नाकांडी सीट से मैदान में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में धुबरी सीट से मिली करारी हार के बाद अजमल के लिए यह चुनाव साख की लड़ाई बन गया है। पार्टी के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 2016 में एआईयूडीएफ ने 13 सीटें जीती थीं, जबकि 2021 में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर यह आंकड़ा 15 तक पहुंचा था। इस बार 2026 के चुनाव में पार्टी ने 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। असम की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम यह तय करेंगे कि असम की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी।

खाड़ी युद्ध से गहराते पेट्रोलियम संकट के बीच यूपी में गोबर गैस बनेगी राहत का जरिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। मध्य पूर्व में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल पैदा कर दी है। युद्ध की इन परिस्थितियों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बाधित होने का खतरा मंडरा रहा है। इस संभावित संकट को भांपते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया है। सरकार की योजना प्रदेश भर की गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट (बायोगैस) स्थापित कर एलपीजी रसोई गैस का एक ठोस विकल्प तैयार करने की है।

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में संचालित सभी 7,527 गौशालाओं और गो-आश्रय स्थलों को ऊर्जा उत्पादन के केंद्रों में बदला जाएगा। वर्तमान में राज्य के इन केंद्रों में लगभग 12.39 लाख गोवंशीय पशु मौजूद हैं। अब तक इन गौशालाओं से प्राप्त गोबर का मुख्य उपयोग केवल जैविक खाद या कंपोस्ट बनाने तक सीमित था, लेकिन अब इसके एक-एक अंश का उपयोग ईंधन उत्पादन के लिए किया जाएगा। वर्तमान में 80 बड़ी गौशालाओं में बायोगैस प्लांट पूरी तरह क्रियाशील हैं, जिन्हें सफलता के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को मिशन मोड पर चलाने के निर्देश दिए हैं। योजना का उद्देश्य न केवल ईंधन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को रसोई गैस की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी से राहत दिलाना भी है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी।

रणनीति के अनुसार, पहले चरण में सरकारी और संरक्षित गौशालाओं में प्लांट लगाए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में व्यक्तिगत पशुपालकों को भी इस दायरे में लाया जाएगा। आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में 6,433 अस्थायी गौशालाओं में 9.89 लाख, 518 वृहद गो-संरक्षण केंद्रों में 1.58 लाख और कान्हा व कांजी हाउस जैसे केंद्रों में हजारों गोवंश पल रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत भी लाखों गोवंश पशुपालकों के पास हैं, जिन्हें इस श्रृंखला से जोड़ने की तैयारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि खाड़ी देशों में छिड़ा युद्ध यदि लंबा खींचता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है, तो उत्तर प्रदेश का यह स्वदेशी विकल्प आम जनता के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा। इससे न केवल कचरे का सही प्रबंधन होगा, बल्कि गांवों में ऊर्जा के सस्ते और सुलभ स्रोत उपलब्ध होंगे।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधुनिक भारत की नई उड़ान

सौरभ वार्ष्णेय

अप्रैल के अंत में फ्लाइट्स शुरू होने के बाद यह देश का पांचवां सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। चारों फेज का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। 5000 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल में एयरपोर्ट का विस्तार होगा। पहले फेज के बाद इस एयरपोर्ट पर यात्री क्षमता करीब 1.2 करोड़ होगी। फाइनल फेज पूरी होने के बाद यह 7 करोड़ से अधिक यात्री क्षमता वाला एयरपोर्ट होगा। उड़ानें शुरू होने के बाद तेजी से बढने. की उम्मीद है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की विकास यात्रा का एक बड़ा आधार बनने जा रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके माध्यम से प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई मिलेगी। इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधुनिक भारत की नई उड़ान माना जा रहा है। इस विकास से प्रदेश का ही नहीं देश का विकास भी संभव हो सकेगा? देश की तरक्की में कम्युनिकेशन यानी यातायात को सुगम बनाना स्वाभाविक ही वह क्षेत्र और देश स्वयं तरक्की के पंख लगा लेता है। आज उसी अध्याय में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को बीमारूइ छवि से बाहर निकालेगा। प्रदेश की छवि में चार चांद लगेंगे

जैसा की बताया जा रहा है अप्रैल के अंत में फ्लाइट्स शुरू होने के बाद यह देश का पांचवां सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। चारों फेज का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। 5000 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल में एयरपोर्ट का विस्तार होगा। पहले फेज के बाद इस एयरपोर्ट पर यात्री क्षमता करीब 1.2 करोड़ होगी। फाइनल फेज पूरी होने के बाद यह 7 करोड़ से अधिक यात्री क्षमता वाला एयरपोर्ट होगा। उड़ानें शुरू होने के बाद तेजी से बढने. की उम्मीद है। भविष्य का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने की पूरी क्षमता रखता है। इससे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को 'बीमारूइ छवि से बाहर निकालकर 'विकसित प्रदेशइ की दिशा में ले जाने की क्षमता रखता है। और जब देश का सबसे बड़ा राज्य आर्थिक रूप से सशक्त होगा, तो स्वाभाविक है कि भारत की समग्र प्रगति भी तेज होगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) का उद्घाटन होने के बाद अब अप्रैल माह के अंत तक उड़ाने शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 65 शहरों के लिए उड़ान शुरू किए जाने का दावा है। पहले चरण में देश के 10 शहरों के लिए सेवा शुरू होगी। शुरूआत में केवल घरेलू और कार्गो उड़ानें ही संचालित होंगी। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही यूपी पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वैसे तो देश में एयरपोर्ट अलग-अलग मानकों के आधार पर तय किए जाते हैं। इनमें यात्री क्षमता, क्षेत्रफल और उड़ानों की संख्या शामिल होती है। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के आधार पर सबसे बड़ा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहीं, क्षेत्रफल के लिहाज से हैदराबाद एयरपोर्ट सबसे बड़ा है। उड़ानों की दृष्टि से सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इसे सबसे बड़ा माना जाएगा। देश के पांच सबसे बड़े एयरपोर्ट होगा।

सबसे पहले, यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार और निवेश के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करेगा। अभी तक दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर अत्यधिक दबाव रहता है, लेकिन जेवर एयरपोर्ट उस दबाव को कम करेगा और क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इससे निर्यात, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा, यह परियोजना रोजगार के विशाल अवसर पैदा करेगी। निर्माण चरण से लेकर संचालन तक लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। आसपास के क्षेत्रों—जैसे ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़—में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। तीसरा, यह एयरपोर्ट 'मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटीइ का केंद्र बनेगा। एक्सप्रेसवे, मेट्रो और रेल नेटवर्क से जुड़कर यह क्षेत्र एक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित होगा। इससे किसानों, छोटे व्यापारियों और उद्योगों को अपने उत्पाद देश-विदेश तक पहुंचाने में आसानी होगी।चौथा, विदेशी निवेश को आकर्षित करने में यह अहम भूमिका निभाएगा। जब वैश्विक कंपनियां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देखती हैं, तो वे निवेश के लिए अधिक इच्छुक होती हैं। इससे 'मेक इन इंडियाइ और 'आत्मनिर्भर भारतइ जैसे अभियानों को मजबूती मिलेगी।

हालांकि, विकास के इस मॉडल में कुछ चुनौतियां भी हैं—जैसे पर्यावरण संतुलन और स्थानीय लोगों के पुनर्वास के मुद्दे। इनका संवेदनशील और संतुलित समाधान जरूरी है, ताकि विकास समावेशी और टिकाऊ बन सके।

उत्तर प्रदेश लंबे समय से अपनी विशाल जनसंख्या, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और सीमित औद्योगिक विस्तार के कारण विकास की चुनौतियों से जूझता रहा है। ऐसे में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण न केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना है, बल्कि यह राज्य की आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखने वाला ऐतिहासिक कदम है।सबसे पहले, यह एयरपोर्ट क्षेत्रीय और वैश्विक कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। दिल्ली-एनसीआर के बढ़ते दबाव को कम करते हुए यह नया हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन और निवेश को आकर्षित करेगा। जब दुनिया के बड़े शहरों से सीधी उड़ानें जुड़ेंगी, तो विदेशी कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश करना अधिक आसान और लाभदायक होगा।दूसरा महत्वपूर्ण पहलू रोजगार का है। एयरपोर्ट के निर्माण से लेकर उसके संचालन तक लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। होटल, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खुलेंगी। आसपास के क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्योगों को भी गति मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।तीसरा, यह परियोजना औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों को इस एयरपोर्ट से सीधा लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में यह क्षेत्र तेजी से उभर सकता है। हालांकि, हर बड़े विकास के साथ चुनौतियां भी आती हैं। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय समुदायों के पुनर्वास जैसे मुद्दों को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ संभालना होगा। यदि इन पहलुओं की अनदेखी हुई, तो विकास का यह मॉडल असंतुलित हो सकता है। यह कहना अतिश्योक्ति होगा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नहीं, बल्कि आर्थिक पुनर्जागरण का माध्यम बन सकता है। यदि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर इसे योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं, तो यह राज्य को न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर नई पहचान दिला सकता है।

यूपी को 'बीमारू छवि से बाहर निकालेगा

उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि उत्तर भारत के लिए विकास का नया इंजन बनने जा रहा है।सबसे बड़ी विशेषता इसकी वृहद क्षमता और चरणबद्ध विस्तार योजना है। पूर्ण रूप से विकसित होने पर यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा। शुरूआत में ही इसकी रनवे क्षमता और यात्री संभालने की व्यवस्था इसे भविष्य के दबाव के लिए तैयार बनाती है। अहम विशेषता है इसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी। यह एयरपोर्ट दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बड़े हिस्सों को सड़क, रेल और मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा। इससे न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि व्यापार और उद्योग को भी नई गति मिलेगी। अन्य खासियत है इसका ग्रीन और सस्टेनेबल डिजाइन। यह भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने की दिशा में है, जो पूरी तरह से नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। सोलर एनर्जी, जल संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण इसे भविष्य के एयरपोर्ट्स का मॉडल बनाते हैं। इसके अलावा, यह एयरपोर्ट कार्गो हब के रूप में भी उभरेगा। कृषि, और निर्यात आधारित उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी। इससे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सामाजिक दृष्टि से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में रोजगार सृजन, शहरीकरण और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे आसपास के जिलों का समग्र विकास संभव होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना नहीं, बल्कि नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है। यदि इसे समयबद्ध और संतुलित तरीके से पूरा किया गया, तो यह उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की आर्थिक उड़ान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है, समाचार पत्र व पत्रिकाओं में समसमायिक विषयों पर चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

संपादकीय

सोशल मीडिया पर अंकुश

अमेरिका में लॉस एंजेलिस की एक जूरी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के घातक प्रभावों से त्रस्त एक युवती के पक्ष में सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले से दुनिया भर के अभिवावकों को राहत मिली है। दरअसल, सोशल मीडिया की लत लगाने से जुड़े एक मामले में मेटा और यूट्यूब पर 56 करोड़ का जुमार्ना लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि एक युवती ने मेटा और यूट्यूब पर आरोप लगाया था कि इनकी वजह से उसे सोशल मीडिया की घातक लत लगी। हालांकि, अब तक ये कंपनियां दलील देती रही हैं कि वे मात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और इसकी सामग्री के लिये जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन कोर्ट में वकीलों ने पीड़िता के पक्ष में दलील दी कि जानबूझकर इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं ताकि उपयोगकर्ता कथित सोशल मीडिया की लत के शिकार बन जाएं। शुरूआत से पहचान गुप्त रखने वाली बीस वर्षीय युवती केली के वकीलों की दलील को जूरी ने स्वीकार किया कि इस लत से उसकी मानसिक सेहत को नुकसान हुआ है। जूरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की दलीलों को दरकिनार करते हुए मेटा और यूट्यूब पर साठ लाख अमेरिकी डॉलर यानी छप्पन करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है। जूरी ने माना कि गूगल तथा मेटा ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के संचालन में अपने मुनाफे के मद्देनजर अनुचित उपायों का सहारा लिया है। जूरी ने इसे अनैतिक भी बताया। जूरी के निर्णय के अनुसार इस मामले में जुमार्ने की सत्तर फीसदी राशि मेटा तथा तीस फीसदी रकम गूगल को चुकानी होगी। उल्लेखनीय है कि पूरी दुनिया में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विरुद्ध हजारों मुकदमें चल रहे हैं। जिसमें कई वे लोग भी शामिल हैं जिनके बच्चों ने सोशल मीडिया की लत का शिकार होकर आत्मघाती कदम उठाये हैं। ब्रिटेन समेत कई देशों में अभिभावक इस लत से बच्चों को बचाने के लिये आंदोलन करते रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका में ही विभिन्न अदालतों में सोशल मीडिया के घातक प्रभावों से बच्चों को बचाने के लिये सैकड़ों मामले चल रहे हैं। विश्वास किया जा रहा है कि इस मुकदमे के फैसले का प्रभाव उन तमाम मामलों में भी पड़ सकता है, जो दुनिया के विभिन्न देशों में चल रहे हैं। हालांकि, दोषी पाये गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कर्ताधर्ता इस फैसले से असहमति जताते हुए इसके खिलाफ अपील करने की बात कर रहे हैं। उनकी दलील है कि किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव के अनेक अन्य कारण हो सकते हैं, जिसके लिये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यूट्यूब के अधिकारियों का कहना है कि ये सोशल मीडिया साइट नहीं, सिर्फ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। जबकि पीड़ित युवती के वकीलों की दलील थी कि मेटा आदि कंपनियों ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की संरचना ऐसी बनायी है कि किशोरों को इसकी आदत लग जाए। हकीकत ये है कि भारत समेत दुनिया के करोड़ों किशोर इसकी लत के शिकार बन रहे हैं।

चिंतन-मनन

दूर करें अध्यात्म विद्या का अभाव

अध्यात्म विद्या के विषय में अधिकांश भौतिक विद्वान शिक्षा को ही विद्या मान बैठते हैं। वे विद्या और शिक्षा के अंतर को भी समझने में असमर्थ हैं जबकि विद्या और शिक्षा में धरती और आसमान का अंतर है। इस विषय को स्पष्ट करते हुए महात्मा परमचेतनानंद ने अपने प्रवचन में कहा कि शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना। भौतिक शिक्षा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है जिसका संबंध ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों व मन बुद्धि तक सीमित है। इसके अतिरिक्त विद्या शब्द विद् धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना अर्थात वास्तविक ज्ञान।

यह ज्ञान स्वयं अंदर से प्रकट होता है, इसे ही अध्यात्म ज्ञान कहा जाता है। इसे आत्मा की गहराई में पहुंचने पर ही जाना जाता है। शिक्षा के विद्वान अहंकार से ग्रसित होते हैं, उनमें विनम्रता का अभाव होता है जबकि विद्या का प्रथम गुण विनम्रता है। विद्या वास्तव में मानव की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है।

इस अध्यात्म विद्या से मानव निष्काम कर्म योगी बनता है जो सभी को समान भाव से देखता है। पहले निष्काम कर्म योगी को ही प्रजा अपना राजा चुनती थी। वे अपने पुत्र तथा अन्य प्रजा के साथ समान रूप से न्याय करते थे। आज के असमय में अध्यात्म विद्या का अभाव होने के कारण राजा और प्रजा दोनों ही अशांत हैं फिर भी इसे ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जबकि अध्यात्म विद्या के वेत्ता तत्वदर्शी संत आज भी मौजूद हैं।

मध्य पूर्व तनाव का असर, लेकिन भारत तैयारः संसाधनों का संयमित उपयोग अनिवार्य

सुनील कुमार महला

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण विश्व के कई हिस्सों में पिछले कुछ समय से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे ऊर्जा संकट की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ऐसे समय में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, असीमित नहीं। इसलिए उनका उपयोग सोच-समझकर और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अनावश्यक रूप से बर्बाद करने का अधिकार किसी को नहीं है।

इसी संदर्भ में भारत सरकार ने 26 मार्च 2026 (गुरुवार) को यह स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक और दुष्प्रचारपूर्ण खबरों पर ध्यान न दें, क्योंकि इनका उद्देश्य केवल भय और घबराहट पैदा करना है।पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, भारत के पास कुल 74 दिनों की भंडारण क्षमता है, जिसमें वर्तमान में लगभग 60 दिनों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इस भंडार में कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद तथा भूमिगत रणनीतिक भंडारण शामिल हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि मध्य-पूर्व संकट के 27वें दिन तक देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सरकार के अनुसार, हर नागरिक के लिए लगभग दो महीने तक निरंतर ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित है, चाहे वैश्विक परिस्थितियां कैसी भी हों। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अगले दो महीनों के लिए कच्चे तेल की खरीद पहले से ही सुनिश्चित कर ली है। इतना ही नहीं, मीडिया के हवाले से यह भी खबरें आई हैं कि सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पेट्रोल-डीजल पर ?10 की कटौती की गई है, इससे फिलहाल पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों और आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए कर दिया गया है तथा डीजल पर यह ड्यूटी पूरी तरह खत्म यानी जीरो कर दी गई है। बहरहाल, जहां कुछ देशों में ईंधन की कीमतों में वृद्धि, राशनिंग और पेट्रोल पंपों के बंद होने जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, वहीं भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और किसी आपातकालीन कदम की आवश्यकता भी नहीं पड़ी है।बहरहाल, यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि संकट की इस घड़ी में समाज की वास्तविक परीक्षा एकजुटता और जिम्मेदारी में निहित होती है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ा संकट आता है-चाहे वह महामारी हो, प्राकृतिक आपदा या आर्थिक मंदी-तब केवल आम जनता ही नहीं, बल्कि प्रशासन और व्यापारिक वर्ग की जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ जाती है। दुर्भाग्यवश, ऐसे समय में कालाबाजारी और मुनाफाखोरी जैसी प्रवृत्तियां भी उभरती हैं, जो कृत्रिम कमी पैदा कर आम लोगों की कठिनाइयों को और बढ़ा देती हैं। वास्तव में,कालाबाजारी और मुनाफाखोरी समाज की आर्थिक व्यवस्था को भीतर से खोखला कर देती हैं।यह न केवल आम जनता की जेब पर बोझ डालती है, बल्कि विश्वास की नींव को भी कमजोर करती है। आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतें बढ़ाना नैतिक और कानूनी दोनों रूप से गलत है।सच तो यह है कि ऐसे समय में गरीब और मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ऐसे में सरकार को सख्त कानून और प्रभावी निगरानी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। साथ ही, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई से ही इसका सही समाधान संभव है। जनता को भी जागरूक रहकर ऐसे कृत्यों का विरोध करना चाहिए।ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ व्यापार करना ही स्वस्थ समाज की पहचान है।वास्तव में, हमें यह समझना होगा कि वास्तविक शक्ति संसाधनों को जमा करने में नहीं, बल्कि उन्हें जरूरतमंदों तक सही तरीके से पहुंचाने में है। कालाबाजारी भले ही अल्पकालिक लाभ दे, लेकिन यह समाज के विश्वास और नैतिक आधार को कमजोर करती है। इसके विपरीत, यदि व्यापारी, उद्योगपति, प्रशासन और आम नागरिक मिलकर ईमानदारी, पारदर्शिता और सहयोग का मार्ग अपनाएं, तो किसी भी संकट के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अंततः, यही समय है जब हमें यह सिद्ध करना होगा कि हमारी सभ्यता स्वार्थ पर नहीं, बल्कि एकता, संवेदना और सहभागिता जैसे मूल्यों पर आधारित है। यही भावना न केवल संकट से उबरने में सहायक होती है, बल्कि एक मजबूत और सुदृढ़ राष्ट्र की नींव भी रखती है।

वैश्विक ऊर्जा संकट बनाम लॉकडाउन की आशंका?

किशन सनमुखदास

क्या दुनियाँ फिर कोविड-19 जैसे दौर की ओर बढ़ रही है या यह केवल भय और अफवाहों का जाल है?

क्या दुनियाँ एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है?- अफवाह बनाम जमीनी हकीक- भय,भ्रम और बदलती वैश्विक वास्तविकता

पीएम की लगातार बैठकें,देश में तेल,गैस और अन्य आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति लगातार सुनिश्चित करना -अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी को ध्यान में रखना जरूरी

वैश्विक स्तरपर कोविड -19 महामारी ने दुनियाँ को जिस तरह से झकझोर कर रख दिया था,उसकी स्मृतियाँ आज भी लोगों के मन में ताजा हैं। 2020-21 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन,आर्थिक गतिविधियों का ठप होना,सड़कों पर सन्नाटा और अनिश्चित भविष्य ये सब अनुभव आज भी समाज की सामूहिक चेतना में गहराई से बसे हुए हैं।ऐसे में जब 2026 में ऊर्जा संकट, पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और सरकारों की लगातार बैठकों की खबरें सामने आती हैं,तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में यह सवाल उठता है,क्या दुनियाँ एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है? क्या यह एक नए प्रकार का ऊर्जा लॉकडाउन होगा? या यह केवल अफवाहों औरसोशल मीडिया की उपज है? मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहता हूं कि इस बार संकट का कारण कोई वायरस नहीं,बल्कि ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी अनिश्चितताएँ हैं।पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका ने कई देशों को सतर्क कर दिया है। कुछ देशों में बिजली की खपत कम करने के लिए स्कूल-कॉलेजों को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है,सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में केवल चार दिन काम का मॉडल अपनाया जा रहा है, और वर्क फ्रॉम होम को फिर से प्रोत्साहित किया जा रहा है।यह स्थिति भले ही कोविड जैसी स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है, लेकिन इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उतने ही गहरे हो सकते हैं।श्रीलंका जैसे देशों में पहले से ही ऊर्जा संकट के कारण सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि ऊर्जा संकट केवल आर्थिक समस्या नहीं है,बल्कि यह सामाजिक स्थिरता और नागरिक जीवन को भी सीधे प्रभावित करता है।भारत की स्थिति की व्याख्या हम,सतर्कता लेकिन घबराहट नहीं के रूप में कर सकते हैं,भारत भी इस वैश्विक संकट को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। पीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 26 मार्च 2026 को शाम साढ़े छह बजे बैठक कर स्थिति की समीक्षा की है।इन बैठकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में तेल,गैस और अन्य आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत के पास लगभग 60 दिनों का ईंधन भंडार उपलब्ध है, जो तत्काल किसी बड़े संकट की संभावना को कम करता है।सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में किसी प्रकार का लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है।वित्त मंत्री संसदीय कार्य मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री ने संयुक्त रूप से बयान देकर इन अफवाहों को खारिज किया है। भारत में लॉकडाउन के संदेह का जन्म संसद में पीएम के बयान की गलत व्याख्या,अफवाहों के कारण कुछ जगहों पर पैनिक बाइंग की स्थिति उत्पन्न हुई, इंडियन ऑइल कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम ने सफाई दी हैसरकार का स्पष्ट संदेश है कि देश में पर्याप्त फ्यूल स्टॉक मौजूद है। लॉकडाउन और फ्यूल क्राइसिस की खबरें पूरी तरह भ्रामक है सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी से सतर्क रहने की अपील की गई है। 27 मार्च 2026 को भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है और ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीयमंत्री ने सोशल मीडिया पर चल रही लॉकडाउन की खबरों को पूरी तरह गलत और हानिकारक बताया है। लोग घबराएं नहीं और न ही अफवाहों पर ध्यान दें, क्योंकि ईंधन और जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है।

साथियों बात अगर हम सोशल मीडिया और अफवाहों का तंत्रः डर का नया स्रोत इसको समझने की करें तो आज के डिजिटल युग में सूचना जितनी तेजी से फैलती है,उतनी ही तेजी से भ्रम और अफवाहें भी फैलती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऊर्जा लॉकडाउन और देशव्यापी बंदी जैसे शब्द ट्रेंड करने लगे,जिससे आम लोगों में डर का माहौल बन गया।पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगने लगीं,गैस सिलेंडर और आवश्यक वस्तुओं की खरीद अचानक बढ़ गई।यह स्थिति बताती है कि संकट केवल वास्तविक नहीं होता, बल्कि उसकी धारणा भी उतनी ही प्रभावशाली होती है। जब लोग यह मान लेते हैं कि कोई बड़ा संकट आने वाला है,तो उनका व्यवहार भी उसी अनुसार बदल जाता है,चाहे वास्तविक स्थिति उतनी गंभीर न हो।

साथियों बात अगर हम भारत की रणनीतिः संतुलन और स्थिरता को समझने की करें तो भारत ने पिछले कुछवर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में विविधीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा पर बढ़ता जोर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, और आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण ये सभी कदम भारत को इस प्रकार के संकटों से निपटने में सक्षम बनाते हैं।सरकार का वर्तमान फोकस स्पष्ट हैःआपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना,कीमतों को नियंत्रित रखना,जनता में घबराहट को रोकना,जनता की भूमिका-संयम और जागरूकता-किसी भी संकट के दौरान सरकार की नीतियों के साथ-साथ जनता का व्यवहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि लोग अफवाहों पर विश्वास करके अनावश्यक खरीददारी करते हैं, तो इससे कृत्रिम संकट उत्पन्न हो सकता है।इसलिए यह आवश्यक है कि लोग केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें।

साथियों बात अगर हम राजनीतिक बयानबाजी और उसके प्रभाव को समझने की करें तो,इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक बयानबाजी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक बार फिर लॉकडाउन लगा सकती है और लोगों को घरों में कैद कर सकती है।उन्होंने 2021 के लॉकडाउन और चुनावों का उदाहरण देते हुए अपनी बात रखी।हालांकि, ऐसे बयान अक्सर राजनीतिक दृष्टिकोण से दिए जाते हैं,लेकिन इनका असर आमजनता पर गहरा पड़ता है। जब एक वरिष्ठ नेता इस तरह की आशंका व्यक्त करता है, तो लोगों के मन में अनिश्चितता और भय और अधिक बढ़ जाता है।

साथियों बात अगर हम पीएम के संसद में बयान और उसके गलत अर्थ को समझने की करें तो,सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया गया कि पीएम ने संसद में अपने संबोधन के दौरान लॉकडाउन का संकेत दिया था।लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने केवल कोविड-19 महामारी का उदाहरण देते हुए यह कहा था कि हमें हर प्रकार की चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बयान को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई।यह घटना यह दशार्ती है कि किस तरह आधी-अधूरी जानकारी या संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किए गए बयान बड़े पैमाने पर सटीक रूप से गलतफहमी पैदा कर सकते हैं।

साथियों बात अगर हम,क्या वैश्विक स्तरपर ऊर्जा लॉकडाउन संभव है? इसको समझने की करें तो,ऊर्जा लॉकडाउन का विचार नया है, लेकिन पूरी तरह असंभव नहीं। यदि ऊर्जाआपूर्ति में भारी कमी आती है,तो सरकारें बिजली और ईंधन की खपत को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रतिबंधात्मक उपाय लागू कर सकती हैं।हालांकि, यह कोविड-19 जैसे पूर्ण लॉकडाउन से अलग होगा।ऊर्जा संकट के दौरान संभावित उपायों में शामिल हो सकते हैंः(1)औद्योगिक गतिविधियों को सीमित करना (2) कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना (3) सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देना (4) बिजली और ईंधन की खपत परनियंत्रण लेकिन इन उपायों का उद्देश्य जीवन को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना होगा।

संक्षिप्त समाचार

मार्ग के शेष निर्माण की मिली स्वीकृति

श्रीनगर गढ़वाल : कीर्तिनगर ब्लॉक के अंतर्गत स्यालसौड़, पनियाली होते हुए बणतोलीखाल से नैलचामी तक प्रस्तावित मार्ग के शेष निर्माण कार्य को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। करीब छः किमी. मार्ग के एक किमी. से अधिक के हिस्से का निर्माण कार्य लंबे समय से रुका हुआ था। अब इसके निर्माण के लिए 41 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने बताया कि इस मार्ग के बनने के बाद कीर्तिनगर के धारी ढुंडसिर क्षेत्र से घनसाली नैलचामी क्षेत्र की दूरी कम हो जाएगी एवं लोगों को आवागमन की सुलभ सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि बडियारगढ़ क्षेत्र के लोगों की नैलचामी क्षेत्र के गांवों में रिश्तेदारी है। अब इस मार्ग के शेष निर्माण की स्वीकृति मिलने से आवाजाही भी आसान हो जाएगी। उन्होंने लोनिवि को जल्द शेष मार्ग की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। (एजेंसी)

हंस फाउंडेशन ने फिताड़ी अग्नि पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री

नई टिहरी। मोरी ब्लॉक के फिताड़ी गांव में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए हंस कल्चर सेंटर एवं हंस फाउंडेशन आगे आए। संस्था की ओर से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई जिसमें खाद्य सामग्री के साथ–साथ कंबल भी शामिल रहे। इस सहयोग से संकट की घड़ी में जूझ रहे परिवारों को बड़ी राहत मिली। शनिवार को हंस कल्चर सेंटर और हंस फाउंडेशन के सदस्यों ने फिताड़ी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने अग्नि पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री बांटी। वहीं, पीड़ित परिवारों के चेहरों पर कुछ हद तक सुकून देखने को मिला। ग्रामीणों ने भी हंस फाउंडेशन की इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार का सहयोग आपदा से उबरने में बेहद सहायक साबित होता है। हंस फाउंडेशन के वरिष्ठ सेवक किशन रावत ने बताया कि संस्था सदैव समाज सेवा के लिए समर्पित रही है और भविष्य में भी जरूरतमंदों की हरसंभव सहायता करती रहेगी।

मेधावी छात्र–छात्राओं को किया गया पुरस्कृत

नई टिहरी। गुरु रामराय पब्लिक स्कूल थत्यूड़ का वार्षिकोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया। मेधावी छात्र–छात्राओं को प्रशस्तिपत्र और उपहार देकर सम्मानित किया। वार्षिकोत्सव का राजकीय महाविद्यालय थत्यूड़ के प्राचार्य बिजेंद्र लिंगवाल, विद्यालय के प्रधानाचार्य दिवाकर थपलियाल, प्रबंध समिति की अध्यक्ष विनीता रावत ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। छात्र–छात्राओं ने जौनपुरी तांदी, रासो, हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी गीतों पर सुंदर प्रस्तुति देकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। मुख्य अतिथि प्राचार्य लिंगवाल ने छात्र–छात्राओं से मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा। मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक 97 6 अंक प्राप्त कर पहले स्थान पर रहे गौरव भंडारी, 94 प्रतिशत अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही वेदिका तथा 92 9 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान रहने वाले कार्तिक पंवार को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीईओ सुनील कार्गी, सुनील थपलियाल, गीता राणा, ग्राम प्रधान रामदयाल, कामनी देवी, स्वाती देवी, कृष्णा देवी, मनीषा देवी, नीलम देवी, सविता देवी आदि मौजूद थे।

जर्जर पुल से आवाजाही करने को छात्र मजबूर

नई टिहरी। तहसील के बंचाणगांव और चपटाड़ी गांव के बीच मैड़ा खड्ड पर बना वर्षों पुराना पैदल पुल अब पूरी तरह जर्जर हो गया है। पुल की खराब स्थिति के कारण यहां से गुजरने वाले ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को हर वक्त खतरा सताता है। लंबे समय से पुल के पुनर्निर्माण की मांग के बावजूद अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बंचाणगांव से करीब 40 छात्र–छात्राएं प्रतिदिन राजकीय इंटर कॉलेज सरनौल पढ़ने जाते हैं जिन्हें मजबूरन इसी जर्जर पुल से होकर गुजरना पड़ता है। इन दिनों खड्ड में पानी कम होने के कारण कुछ लोग सीधे खड्ड से आवाजाही कर लेते हैं लेकिन बरसात में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। पानी बढ़ने और तेज बहाव के चलते खड्ड से गुजरना असंभव हो जाता है जिससे ग्रामीणों और छात्रों को जान जोखिम में डालकर पुल का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्षेत्र में कोई वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नहीं है। ग्राम प्रधान उपेंद्र रावत ने बताया कि पुल के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव आपदा मद से स्वीकृति के लिए जिला प्रशासन के पास लंबित है ।

खुले में बह रहा गंदा नाला, बीमारियों का खतरा

कोटद्वार के काशीरामपुर तल्ला में खुले में बहता गंदा नाला

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : नगर क्षेत्र की गंदगी को ढोते हुए काशीरामपुर तल्ला में बह रहा नाला आमजन के लिए मुसीबत बन रहा है। खुले में बह रहे इस नाले से उठ रही दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों को संक्रामक बीमारियों का खतरा सताने लगा है। कई बार नाला ओवरफ्लो होने के कारण गंदा पानी सड़क पर ही बहने लगता है। नाले को ढकने के लिए स्थानीय लोग कई बार निगम से गुहार भी लगा चुके हैं।

बाजार क्षेत्र से गाड़ीघाट होते हुए काशीरामपुर तल्ला क्षेत्र में बह रहा यह नाला कई स्थानों पर खुले में बह रहा है। जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध का माहौल बना रहता है। गर्मी बढ़ने के कारण ही स्थिति और अधिक विकराल होती जा रही है। दुर्गंध के कारण लोगों का अपने घर व प्रतिष्ठानों में बैठना भी मुश्किल होता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काशीरामपुर क्षेत्र में कई स्थानों पर नाले के ऊपर स्लैब नहीं बनाई गई है। जिससे राह चलते लोगों को नाले में बहती हुई गंदगी दिखाई देती है। नाले में कई बार सीवर का पानी भी बहता रहता है। ऐसे में वार्डवासियों को संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। कहा कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए वह कई बार नगर निगम के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर चुके हैं। लेकिन, हालात जस के तस बने हुए हैं।

दुर्घटनाओं का खतरा

खुले में बह रहे इस नाले से क्षेत्र में दुर्घटनाओं का भी खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ समय पहले सरकारी सिस्टम ने नाले के आसपास लोहे के जाल लगाए थे। लेकिन, कुछ असामाजिक तत्वों ने इन जालों को भी काट दिया है।

ऐसे में राहगीरों के नाले में गिरने का खतरा बना रहता है। सबसे अधिक खतरा रात के अंधेरे में बना रहता है। यदि नाले के ऊपर स्लैब डाल दी जाती है तो सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा।

उपजिलाधिकारी ने किया सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों का निरीक्षण

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : कोटद्वार में उपजिलाधिकारी संदीप कुमार ने शिवपुर क्षेत्र में एक सरकारी सस्ता गल्ला दुकान का औचक निरीक्षण किया।

शनिवार को उपजिलाधिकारी संदीप कुमार शिवपुर स्थित एक सरकारी सस्ता गल्ला दुकान में पहुंचे। दुकान में उपजिलाधिकारी ने वाचक निरीक्षण की पंजिका मांगी, जिस पर गल्ला विक्रेता ने बताया कि वाचक पंजिका पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में जमा की गई है। उपजिलाधिकारी ने शिकायत पंजिका का निरीक्षण किया, जिसमें दो-तीन शिकायतें दर्ज मिली।

मौके पर मौजूद पूर्ति निरीक्षक संजना बिष्ट को समय-समय पर सरकारी संस्था गल्ला विक्रेताओं की दुकान का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही राशन की बिक्री सही न पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए।

समस्याओं पर नागरिक मंच ने जताया रोष

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : अतिक्रमण, पार्किंग सहित विभिन्न समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर नागरिक मंच ने रोष व्यक्त किया है। कहा कि लगातार शिकायत के बाद भी सरकारी सिस्टम समस्याओं को लेकर लापरवाह बना हुआ है। यदि समय पर समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन चलाया जाएगा। जनता की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समस्याओं के संबंध में मंच ने नगर आयुक्त पीएल शाह को ज्ञापन दिया। मंच के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश नैथानी ने कहा कि मंच पिछले लंबे समय से समस्याओं के निराकरण को लेकर संघर्ष कर रहा है। शहर में निराश्रित गोवंश, अवैध अतिक्रमण, पार्किंग, मोटर नगर बस अड्डा सहित दर्जनों ज्वलंत समस्याएं जस की तस बनी हुई है। जिन पर नगर निगम प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। जिसके कारण शहर विकास के क्षेत्र में लगातार पिछड़ता जा रहा है। कहा कि शहर में अतिक्रमण होने से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर निगम क्षेत्र में नियमित रूप से बाहरी क्षेत्रों के लोगों का सत्यापन भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आपराधिक घटनाएं बढ़ने की संभावना है। कहा कि निराश्रित गोवंश के लिए अभी तक स्थाई ठिकाना नहीं बनवाया गया है, जिसके कारण अभी भी बड़ी संख्या में निराश्रित गोवंश सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही है, साथ ही गोवंश चोटिल भी हो रहा है। कहा कि नगर की प्रमुख समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर वरिष्ठ नागरिक संगठन, व्यापार संघ, पूर्व सैनिक लीग, पूर्व सैनिक संगठन, अर्घ सैनिक बल संगठन, ग्रामीण विकास नागरिक मंच सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से दो अप्रैल को गोखले मार्ग के समीप धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

प्रदेश के बेहतर विकास के लिए वन कानून में करना होगा सुधार

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक डा. शक्तिशैल कपरवाण ने कहा कि वन अधिनियम के कारण प्रदेश में कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग भी इसी वन कानून के कारण धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। कहा कि प्रदेश सरकार को वन जीव व वन कानूनों में सुधारीकरण करना चाहिए। कोटद्वार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए डा. शक्ति शैल कपरवाण ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन कानून में सुधार किया जाना चाहिए। राजा जी पार्क और राष्ट्रीय नेशनल कॉर्बेट पार्क के कानून से पीड़ित यमकेश्वर दुगड्डा, द्वारीखाल, नैनीडांडा, जयहरीखाल आदि विकासखण्डों में जंगली जानवरों व वन कानून बाधा बन रहा है। इससे कई क्षेत्रों में विकास नहीं हो पा रहा है। जिससे ग्रामीण पलायन के लिए मजबूर हो रहा है। कपरवाण ने सरकार से मांग की है कि आम जनता व उनके पालतू पशुओं को हिंसक जानवरों से रक्षा करने और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों से बचाने के लिए ठोस कानून बनाने चाहिए। ग्रीन बोनस के रूप में पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले प्रति परिवार को बीस हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाए। जिससे वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। उन्होंने पहाड़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को भी बेहतर बनाने की मांग उठाई। कोटद्वार में मेडिकल कालेज निर्माण, अधुनिक बस अड्डा निर्माण की भी मांग उठाई गई। कहा कि स्थानीय जनता लगातार बेहतर सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। इस मौके पर उक्रांद के महानगर अध्यक्ष जग दीपक सिंह रावत, महेंद्र सिंह रावत, सत्यपाल सिंह नेगी, भारत मोहन काला, उमेद सिंह भंडारी, गुलाब सिंह रावत, अंबर कपरवाण आदि मौजूद रहे।

पत्रकारिता विषय पर हुई भाषण प्रतियोगिता में अंशिका रही अव्वल

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार के बीजेएम सी विभाग द्वारा टीआरपी की दौड़ में गिरती पत्रकारिता विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के प्रारंभ में बी जे एम सी विभाग के प्राध्यापक श्री चन्द्रधर कंडवाल ने पत्रकारिता मे कम्युनिकेशन के प्रभाव पर प्रकाश डाला। बीजेएमसी के छात्र कृष्णकांत कुकरेती ने अपने भाषण में ऑनलाइन जर्नलिज्म विषय पर विस्तार से चर्चा की। छात्र सुजल ने यूट्यूब चैनल तथा फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से लोकप्रिय होती जा रही पत्रकारिता पर प्रकाश डाला।

बीजेएमसी के छात्र आयुष धस्माना ने कहा कि आजकल पाठक प्रतिदिन अखबार पढ़ने की बजाय ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यमों से प्राप्त समाचारों की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं। छात्रा आंचल कुकरेती ने कहा कि आजकल कुछ पत्रकार अपनी जिम्मेदारियां भूलते जा रहे हैं और समाज के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। लोग झूठ और सच में अंतर करना भूलते जा रहे हैं, जिससे लोगों की सोच प्रभावित होती जा रही है। बीजेएमसी छात्रा अंशिका बुड़ाकोटी ने कहा कि कई न्यूज़ चैनल अब सही चीजों को दिखाने के स्थान पर भ्रामक एवं झूठी खबरें ज्यादा दिखा रहे हैं। वह पेड न्यूज़ पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे सही खबरें जनता के सामने नहीं आ पा रही हैं। भाषण प्रतियोगिता में अंशिका बुड़ाकोटी ने प्रथम कृष्णकांत कुकरेती ने द्वितीय एवं आंचल कुकरेती ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डी एस नेगी ने कहा कि पत्रकारिता का उद्देश्य केवल टीआरपी बढ़ाना नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए तथा न्यूज़ चैनलों को सच्चाई एवं गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर बी जे एम सी विभाग प्रभारी डॉ० एस० के० गुप्ता ने कहा कि अधिकांश न्यूज़ चैनल टी आर पी बढ़ाने की दौड़ में लगे हुए हैं और जनता को झूठी एवं भ्रामक खबरें परोस रहे हैं, जिससे एक ओर तो पत्रकारिता का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जनता की मूलभूत समस्याओं से संबंधित खबरें पीछे छूटती जा रही। झूठी खबरों के चक्कर में लोगों में भ्रम फैल रहा है एवं कई बार लोग हड़बड़ा कर गलत निर्णय ले बैठते हैं। उन्होंने कहा कि टी आर पी बढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन यह पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए। इस अवसर पर बीजेएमसी प्राध्यापक श्री अरविंद दुदपुड़ी ने टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में मीडिया द्वारा द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा टीआरपी की दौड़ में गिरती पत्रकारिता विषय पर चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम में बीजेएमसी प्राध्यापक अनुपम भारद्वाज ने बताया कि टीआरपी कैसे काम करती है। उन्होंने कहा कि यहां गलती सिर्फ न्यूज़ चैनलों की नहीं है बल्कि श्रोता भी इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं।

भाषण प्रतियोगिता का संचालन बीजेएमसी की छात्रा कुमारी अंशिका बुड़ाकोटी द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुजल नेगी आयुष आंचल कुकरेती कृष्णकांत शुभम राजपूत मोहम्मद मुदस्सिर सुधांशु देवरानी आस्था स्नेहा गोसाई दिव्यांशी आदि छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

लालढांग–चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए आज मनाया जाएगा धिक्कार दिवस

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग को एलिवेटेड बनाने की मांग को लेकर आंदोलनरत आंदोलनकारी 29 मार्च को हल्दूखाता तिराहे पर धिक्कार दिवस मनाएंगे।

चिल्लरखाल वन चौकी के समीप धरना स्थल पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। कहा कि क्षेत्रीय जन लंबे समय से आंदोलन पर डटे हुए हैं। 12 फरवरी को न्यायालय ने मार्ग को बनाने की स्वीकृति दी। लेकिन, अब तक सरकार ने मार्ग निर्माण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। यही नहीं, कुछ दिन पूर्व वन विभाग ने मार्ग पर व्यवसायिक वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी थी। कहा कि सरकार की निष्क्रियता से स्पष्ट है कि सरकार क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर नहीं है। जबकि, जनता के हित को देखते हुए उक्त मार्ग का बनना बहुत आवश्यक है। इस मार्ग के निर्माण से ही क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। साथ ही शहरवासियों को राजधानी देहरादून जाने के लिए राज्य का ही मार्ग मिलेगा। इस मौके पर रवींद्र सौंद, जीवानंद शर्मा, गोवर्धन काला, नरेंद्र सिंह, स्वयंभर सिंह, मोहन जोशी, कल्पना जोशी, प्रेमा बजेठा, शांति सहित अन्य मौजूद रहे।

कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत चिल्लरखाल चैक पोस्ट के समीप धरना देते स्थानीय लोग

शहीद भगत सिंह को किया याद

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन ने शहीद भगत सिंह के योगदान को याद किया। कहा कि देश की आजादी में दिए गए शहीद भगत सिंह के योगदान को कभी भुलाया नही जा सकता।व्यापार मंडल सभागार में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का अयोजन किया गया।

लोगों ने शहीद भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि देश की आजादी के लिए भगत सिंह ने अपना सर्वोच्च त्याग दिया था। शहीद सिंह साम्प्रदायिकता विरोधी और जातिवाद विरोधी थे। वह सदैव मजदूर, मेहनतकश लोगों की आवाज बनते रहे। कहा कि हमें भी देश हित में महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इस दौरान मानवता मंच संगठन का भी गठन किया गया। जिसका संयोजक भूपाल और सह संयोजक गोविंद डंडरियाल को चुना गया। कहा कि जनता के हितों को लेकर इस मंच का गठन किया गया है। इस मौके पर दिनेश, दीपा, कमल आदि मौजूद रहे।

बच्चों में हाथ धोने की आदत बचपन से ही डालना जरूरी

भोजन माताओं को दिया प्रशिक्षण

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : दुगड्डा ब्लॉक की भोजन माताओं को शनिवार को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 50 भोजन माताओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान स्वच्छता, भण्डारण व पोषण सम्बन्धी जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को दी गई। कहा कि बच्चे हाथ धोकर ही खाना खायें, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय।

प्रशिक्षण का शुभारम्भ प्रभारी उप शिक्षा अधिकारी उमाकांत कुकरेती, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सूरज मोहन रावत द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सन्दर्भ दाता राउमावि लालपुर से एमडीएम प्रभारी सहायक अध्यापक श्रीमती पुष्पा वर्मा, राउप्रावि मवाकोट से सहायक अध्यापक सुधीर अग्रवाल ने भोजन माताओं को खाद्यान्न का मानक प्रति छात्र (प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम व उच्च प्रा. स्तर पर 150 ग्राम) के साथ-साथ प्रति छात्र दाल की मात्रा (प्रा. स्तर 20 ग्राम व उ.प्रा. स्तर 30 ग्राम) की जानकारी दी। साथ ही लोह तत्व, आयोडीन, विटामिन्स, मिनरल्स व खनिज लवणों के बारे में बताया गया। स्वच्छ जल के महत्व को समझाया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों में हाथ धोने की आदत बचपन से ही डालना बहुत जरूरी है। खाना खाने के पहले और शौच के बाद हाथ अवश्य धोना चाहिए। हाथ की गंदगी अंदर जाने बीमारियों का शिकार बनना पड़ता है जिससे अनावश्यक चिकित्सा खर्चा होता है।

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार अपनाएं युवा

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिला उद्योग केंद्र की ओर से औद्योगिक कृषि एवं उद्यमिता कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार शुरु करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। आयोजित कार्यशाला के दूसरे दिन का शुभारंभ लैंसडौन विधायक दिलीप सिंह रावत व महापौर शैलेंद्र सिंह रावत ने किया। वक्ताओं ने कहा कि युवाओं को बेहतर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। अधिक से अधिक युवाओं को योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। कहा कि कोटद्वार में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। विशेष रूप से आयुर्वेद, आर्गेनिक उत्पाद, कृषि एवं उद्यान क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने पर भी बल दिया। महापौर शैलेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान समय में तकनीक आधारित उद्योगों की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। युवाओं को समय के साथ नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। उन्होंने ड्रोन तकनीक, पैकेजिंग एवं वैल्यू एडिशन को भविष्य के उद्योगों का आधार बताया। कहा कि इन क्षेत्रों में स्वरोजगार की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों, उद्यमियों एवं संस्थानों की ओर से स्टाल लगाए गए थे। इस मौके पर महाप्रबंधक सोमनाथ गर्ग, नर सिंह कर्णवाल, विवोक चौहान, सुनील गुप्ता आदि मौजूद रहे।

सीएचसी में विशेषज्ञ चिकित्सक होंगे तैनात

श्रीनगर गढ़वाल : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग में वरीयता के आधार पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी टिहरी डॉ. श्याम विजय ने पूर्व प्रधान बमाना रतन सिंह के ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देवप्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हिंडोलाखाल, पौड़ीखाल, जामनीखाल और टकोली स्थित चिकित्सालयों में डॉक्टरों के सभी पद भरे हुए हैं। डॉ. विजय ने बताया कि सीएचसी देवप्रयाग में वर्तमान में एक्स-रे, पैथोलॉजी लैब और सचल चिकित्सा वाहन जैसी आधुनिक सुविधाएं पहले से ही सुचारु रूप से संचालित हैं। अब अस्पताल में स्त्री रोग एवं हड्डी रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। (एजेंसी)

बेहतर स्वास्थ्य के लिए खनपान पर दें विशेष ध्यान

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : नजीबाबाद रोड स्थित आर्य कन्या इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य परीक्षण व जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें छात्राओं को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही स्वास्थ्य की भी जांच की गई। कहा कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें खानपान पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

बुरांस संस्था की ओर से आयोजित कार्यशाला में छात्राओं के वजन, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, शुगर आदि जांच की गई। विशेषज्ञों ने छात्राओं को बेहतर खानपान के प्रति जागरूक किया।

कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए हमें खनपान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाजार में खुले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। इससे शरीर में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इस मौके पर बुरांस संस्था के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मदन मोहन भारद्वाज, प्रधानाचार्य रेनू नेगी, उपाध्यक्ष ललिता प्रसाद कोटनाला, योगेश राणा, उमा नेगी, दर्शनी रावत, हेमा अग्रवाल, वंदना कंडारी, विजयलक्ष्मी, रश्मि चौधरी, पुष्पा बलौधी, गरिमा किमोठी आदि मौजूद रहे।

आयोजित शिविर में बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच करते विशेषज्ञ

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार का औचक निरीक्षण किया

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वारः उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में आज विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री खेराज भट्ट ने प्राचार्य प्रोफेसर डी.एस. नेगी के साथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , कोटद्वार का परीक्षाओं का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रार श्री भट्ट और प्राचार्य प्रो. नेगी ने संयुक्त रूप से परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा हॉल का भ्रमण कर परीक्षार्थियों की सुविधाओं और सुरक्षा मानकों की बारीकी से समीक्षा की और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संचालन पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों और परीक्षा ड्यूटी में तैनात समस्त स्टाफ के अनुशासन व कुशल प्रबंधन की सराहना की।

प्राचार्य प्रोफेसर डी.एस. नेगी ने रजिस्ट्रार को आश्वस्त किया कि महाविद्यालय में परीक्षाओं का संचालन शासन और विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप पूरी कड़ाई के साथ किया जा रहा है। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार खेराज भट्ट द्वारा परीक्षा संचालन पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर उत्तरखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर पीजी कॉलेज कोटद्वार की कोडिनेटर डॉ0 राखी डिमरी तथा डॉ0 कपिल थपलियाल उपस्थित रहे।

बिटिया जन्मोत्सव कार्यक्रम : गीता सैलानी द्वारा लाभार्थियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार :महिला मिलन केन्द्र चैलूसैण में बिटिया जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया ,जिसके अंतर्गत श्रीमती विनीता भंडारी ग्राम प्रधान सुराड़ी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संचालित किया गया, बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती प्रीति अरोड़ा एवं सुपरवाइजर श्रीमती गीता सैलानी के द्वारा सभी लाभार्थियों को विभागीय योजनाओं के विषय में विस्तरित जानकारी दी गई ।

संक्षिप्त समाचार

हापला–नैल सड़क पर डामरीकरण कार्य शुरू

चमोली। विकासखंड पोखरी के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली हापला–गुणम–नैल सड़क पर लोनिवि ने डामरीकरण कार्य शुरू कर दिया है। जल्द ग्रामीणों की आवाजाही आसान हो जाएगी। लोनिवि की ओर से सड़क के दो से करीब तीन किमी क्षेत्र में दो करोड़ की लागत से सुधारीकरण कार्य किया जा रहा है। इसके तहत सड़क पर डामरीकरण, नाली निर्माण, स्कपर, कॉजवे आदि कार्य किए जाने हैं। लोनिवि के सहायक अभियंता मो. तस्दीक अहमद और अवर अभियंता दीपक सेमवाल ने मौके पर कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ठेकेदार को गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश दिए। सहायक अभियंता मो. तस्दीक ने बताया कि सड़क पर काम तेजी से चल रहा है। जल्द कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। सड़क के सुधारीकरण से गुणम, मसोली, कुलेडू, नैल, नौली सहित आसपास के अन्य ग्रामीण लाभान्वित होंगे।

नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में युवक गिरफ्तार

चमोली। नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में थाना नंदानगर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 26 मार्च को थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी अपनी शिक्षिका के घर से किताब लेकर लौट रही थी। पुराने बाजार के पुल के पास नंदानगर निवासी एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़खानी कर दी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया। उपनिरीक्षक मनोज भट्ट ने बताया कि आरोपी मनोज कुमार (35) निवासी सैती थाना नंदानगर को गिरफ्तार कर लिया गया।

छात्रों को कॅरिअर की दी जानकारी

रुद्रप्रयाग। राजकीय इंटर कॉलेज कांडई दशज्यूला में छात्र–छात्राओं के लिए कॅरिअर काउंसलिंग शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में कॅरिअर विकल्पों और तैयारियों की जानकारी दी गई। मुख्य वक्ता जिला पंचायत सदस्य एवं अधिवक्ता जयवर्धन कांडपाल ने छात्रों को कानून क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में बताया। आर टेक कंप्यूटर सेंटर के संचालक कालिका प्रसाद कांडपाल ने कहा कि आज के समय में कंप्यूटर और एआई की जानकारी बेहद जरूरी है। उन्होंने छात्रों को नई तकनीकों के साथ अपडेट रहने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य शिव कुमार गांधियन ने छात्रों को पढ़ाई में निरंतरता और अनुशासन बनाए रखने की सीख दी। वहीं एएनएम अंजलि ने स्वास्थ्य क्षेत्र में छात्राओं का मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर एसएमसी अध्यक्ष वीरेंद्र आदि मौजूद रहे।

अगस्त्यमुनि में खुला ऑर्गेनिक स्टोर

रुद्रप्रयाग। टेमरिया निवासी और राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित कृषक कपिल शर्मा ने अगस्त्यमुनि में ऑर्गेनिक स्टोर खोला है। यहां लोगों को ताजी सब्जियां और स्थानीय उत्पाद उपलब्ध होंगे। इस स्टोर के जरिये स्थानीय किसानों के उत्पाद सीधे बाजार तक पहुंच सकेंगे और उन्हें बेहतर दाम भी मिलने की उम्मीद है। कपिल शर्मा ने बताया कि उनकी कोशिश है कि खेत से सीधे लोगों तक ताजे और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पहुंचाए जाएं। आज के समय में स्वस्थ जीवन के लिए ऑर्गेनिक आहार जरूरी हो गया है।

एजेंसी संचालक क्षेत्र में नहीं भेज रहे सिलिंडर के वाहन

चमोली। विकासखंड के 47 गांवों में रसोई गैस सिलिंडरों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में लोग सिलिंडर लेने 15 किमी दूर थराली और 52 किमी दूर नारायणबगड़ के आमसोड़ जा रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि एक सिलिंडर के लिए एक दिन का समय और एक हजार से अधिक की धनराशि अतिरिक्त खर्च हो रही है। वहीं होटलों में बस दोपहर का ही खाना बन रहा है। एजेंसी संचालकों को क्षेत्र में जल्द रसोई गैस सिलिंडर की आपूर्ति करनी चाहिए। विकासखंड मुख्यालय सहित वाण और लोहाजंग तक इंडेन गैस एजेंसी थराली और भारत गैस एजेंसी नारायणबगड़ से रसोई गैस की आपूर्ति होती है। उपभोक्ता इंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, हेमचंद्र ने बताया कि एजेंसी संचालक क्षेत्र में सिलिंडर के वाहन नहीं भेज रहे हैं। ऐसे में पांच सौ से एक हजार रुपये टैक्सी बुक कर सिलिंडर लेने गैस गोदाम जा रहे हैं। व्यावसायिक सिलिंडर नहीं मिलने से होटल व्यवसायी परेशान हैं। सिलिंडर नहीं होने से होटलों में एक टाइम का ही खाना बन रहा है। सुबह का नाश्ता बनना बंद हो गया है। भारत गैस एजेंसी के प्रबंधक संजय ने बताया कि गैस गोदाम में घरेलू सिलिंडर उपलब्ध हैं ।

आम जनमानस को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता : धामी

मुख्यमंत्री ने किया राजस्व लोक अदालत का शुभारम्भ

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में 'राजस्व लोक अदालत' का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाते हुए आम जनमानस को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कहा कि यह पहल न्याय सुलभता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व लोक अदालत का आयोजन वर्षों से लंबित राजस्व विवादों के त्वरित एवं सार्थक समाधान हेतु किया गया है। कहा कि राजस्व संबंधी विवाद केवल कागजी प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि इनके पीछे किसानों की भूमि, परिवारों की आजीविका एवं व्यक्तियों का आत्मसम्मान जुड़ा होता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राजस्व विवादों के निस्तारण हेतु राज्य स्तर पर राजस्व परिषद, मंडल स्तर पर मंडलायुक्त न्यायालय, जिला स्तर पर कलेक्टर न्यायालय तथा तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालय कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रदेश में 400 से अधिक राजस्व न्यायालय संचालित हैं, जिनमें लगभग 50 हजार से अधिक प्रकरण लंबित हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने 'सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि' के मूल मंत्र के साथ 'राजस्व लोक अदालत' की अभिनव पहल प्रारम्भ की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'न्याय आपके द्वार' की अवधारणा को साकार करते हुए प्रदेश के सभी 13 जनपदों में 210 स्थानों पर एक साथ राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 6,933 मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पहल के अंतर्गत भूमि विवादों के अतिरिक्त आबकारी, खाद्य, स्टाम्प, सरफेसी एक्ट, गुंडा एक्ट, सीआरपीसी, विद्युत अधिनियम, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम एवं रेंट कंट्रोल एक्ट से संबंधित मामलों का भी समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण किया जाएगा। बैठक में राजस्व सचिव रंजना राजगुरु भी उपस्थित थीं।

निर्धारित समयसीमा में नामांतरण किया जाए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अविवादित विरासत के मामलों में भू-स्वामी की मृत्यु के पश्चात निर्धारित समयसीमा के भीतर नामांतरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि मृतक की तेहरवीं/पीपलपानी तक वारिसों के नाम नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर नई खतौनी परिवार को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, उन्होंने विवादित भूमि की पैमाइश एवं कब्जों से संबंधित मामलों को एक माह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए।

मौसम विभाग ने तीन अप्रैल तक किया अलर्ट जारी

देहरादून : मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 3 अप्रैल तक का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 29 से 31 मार्च तक राज्य के सभी जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों यानी 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी भी होगी। अप्रैल महीने की शुरुआत भी बारिश से होगी, जिससे मौसम में ठंडक बनी रहेगी। 29 मार्च को पूरे प्रदेश में बारिश होगी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। अन्य जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 30 मार्च को मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दिन उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कई स्थानों पर बारिश और गर्जन के साथ बर्फबारी होगी। मैदानी जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना है। 31 मार्च को भी पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। मैदानी जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और गर्जन की संभावना जताई गई है। अप्रैल की शुरुआत यानी 1 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश होगी, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 2 और 3 अप्रैल को भी पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। (एजेंसी)

चारधाम यात्रा रूट पर पुलिस लगाएगी 100 नए सीसीटीवी कैमरे

नई टिहरी। चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुलिस विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा मार्ग पर पुलिस विभाग 100 नए सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। यात्रा के मुख्य पड़ाव पर ड्रोन कैमरों से निगरानी करेगी। टिहरी जिले में चारधाम यात्रा रूट का करीब 450 किलोमीटर का हिस्सा है। जिले में ढालवाला, मुनिकीरेती और तपोवन यात्रा के मुख्य पड़ाव है। इन पड़ाव पर यात्री वाहनों का अधिक दबाव रहता है। पुलिस यात्रा के दौरान ढालवाला, मुनिकीरेती और तपोवन क्षेत्र में यात्री वाहनों की ड्रोन कैमरों से निगरानी करेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी आयुष अग्रवाल ने बताया कि चारधाम यात्रा व्यवस्थित ढंग से संपादित करने के लिए पुलिस विभाग की ओर से चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले 100 नये सीसीटीवी कैमरे लगायेगी। सभी सीसीटीवी को आसपास के थाना और चौकी के कंट्रोल रूप से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन, बीआरओ, एनएच और लोनिवि के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी। बैठक में यात्रा रूट पर पड़ने वाले सभी डेंजर जोन को ठीक करने को कहा गया है। एसएसपी ने कहा कि यात्रा के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार कर दिया गया है। ढालवाला, मुनिकीरेती और तपोवन क्षेत्रों से प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाने का कार्य चल रहा है। यात्रा रूटों के नये डेंजर प्वाइंट पर अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। रानीपोखरी–गुजराड़ा सड़क पर एक अस्थाई पुलिस चेक पोस्ट बनाई जाएगी। इसके अलावा ढालवाला, व्यासी, कोटी कॉलोनी और घनसाली में एसडीआर की टीम तैनात रहेगी।

मानकों के अनुरूप हो सीवरों का संचालन

चमोली। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने शनिवार को गंगा संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक ली और नदियों को स्वच्छ बनाने को लेकर निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जिले में संचालित सभी सीवर शोधन संयंत्रों का संचालन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार एवं एनजीटी के जल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना चाहिए।डीएम ने निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर हर माह बैठक की जाए जिसमें सीवरेज प्रबंधन व सेप्टेज प्रबंधन की समीक्षा हो। जल संस्थान को सीवर शोधन संयंत्रों का संचालन मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए। डीएम ने परियोजना प्रबंधन, निर्माण व अनुरक्षण इकाई गंगा, उत्तराखंड पेयजल निगम श्रीनगर को निर्देशित किया कि हेमकुंड साहिब व हेमकुंड यात्रा मार्ग पर सीवेज शोधन संयंत्र की संभावना का अध्ययन करें।

प्रशासन ने चार धाम यात्रा में व्यावसायिक उपयोग के लिए ईंधन आपूर्ति के लिए कवायद की शुरु

रसोई गैस के साथ ही वैकल्पिक ईंधन के वितरण की प्रशासन ने बनाई योजना

जयन्त प्रतिनिधि। चमोली : चार धाम यात्रा के दौरान होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों की समस्या के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। प्रशासन की ओर से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों से बैठक कर समस्याओं के निस्तारण की योजना तैयार की जा रही है। प्रशासन की ओर से जनपद के लिए निर्धारित व्यावसायिक रसोई गैस के कोटे के वितरण के साथ ही ईंधन के अन्य विकल्पों को लेकर भी योजना तैयार की है। जिससे यात्रा काल के दौरान होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को व्यवसाय संचालन में परेशानी का सामना न करना पड़े।

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने चार धाम यात्रा की तैयारियों के तहत जिला पूर्ति विभाग, पर्यटन और तहसील के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के सुचारू संचालन में आने वाली संभावित परेशानियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जनपद को मिल रहे व्यावसायिक रसोई गैस के कोटे और बाजार की मांग के अनुरूप ईंधन आपूर्ति को लेकर अन्य विकल्पों को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जनपद में जहां व्यावसायिक रसोई गैस की उपलब्धता के अनुरुप वितरण की प्रणाली बनाई जा रही है। वहीं ईंधन के अन्य विकल्प पिरुल, लकड़ी और पत्थर के कोयले और लकड़ियां होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को उलब्ध करने की भी योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है।जिलाधिकारी ने सभी घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं से ऑन लाइन बुकिंग के माध्यम से रसोई गैस रिफिल करवाने और प्रशासन की ओर बनाई जा रही व्यवस्था में सहयोग की अपील भी की है।

चुनावी मोड में धामी सरकार, तय होगी जवाबदेही

मुख्यमंत्री करेंगे अप्रैल से छः चरणों में 29 विधानसभा क्षेत्रों की चरणवार समीक्षा

देहरादून : प्रदेश में विकास कार्यों को रफ्तार देने के साथ ही अब सरकार भी चुनावी मोड में नजर आने लगी है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अप्रैल में छः चरणों में 29 विधानसभा क्षेत्रों की चरणवार समीक्षा बैठक करेंगे। यह निर्णय केवल प्रशासनिक कवायद भर नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आगामी चुनावों से पहले सरकार के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री धामी इस समय लगातार लंबित परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दे रहे हैं। इस कड़ी में वह अब छः अप्रैल से मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। शासन ने सभी जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे घोषणा पोर्टल पर अद्यतन जानकारी अपलोड कर पूरी तैयारी के साथ प्रस्तुतीकरण दें। यह पहली बार है, जब इतने व्यवस्थित तरीके से सभी घोषणाओं की एक साथ समीक्षा की जा रही है। इससे प्रशासनिक जवाबदेही तय होने के साथ ही राजनीतिक संदेश भी साफ जा रहा है कि सरकार काम के आधार पर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। शासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार छहः अप्रैल को यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडौन और कोटद्वार क्षेत्रों की समीक्षा होगी। सात अप्रैल को थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, जबकि 10 अप्रैल को कुमाऊं के लालकुआं, भीमताल, नैनीताल, कालाढूंगी, काशीपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और रामनगर विधानसभा क्षेत्रों की घोषणाओं की समीक्षा की जाएगी। 13 अप्रैल को डीडीहाट, गंगोलीहाट, कपकोट और बागेश्वर, 15 अप्रैल को सल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर और जागेश्वर तथा 16 अप्रैल को चंपावत क्षेत्र की समीक्षा प्रस्तावित है। साफ है कि मुख्यमंत्री धामी अब घोषणाओं को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई के मूड में नहीं है। समीक्षा के दौरान कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और समयबद्धता पर खास नजर रखी जाएगी। (एजेंसी)

सिमली न्यू मार्केट में एक सप्ताह से नहीं आया पानी

चमोली। नगर क्षेत्र के सिमली न्यू मार्केट में एक सप्ताह से पेयजल आपूर्ति ठप होने से व्यापारी और अन्य लोग पीने के पानी के लिए पिंडर नदी पर आश्रित हैं। सिमली न्यू मार्केट में राड़खी गदेरे से पेयजल की आपूर्ति की जाती है लेकिन एक सप्ताह से पेयजल आपूर्ति ठप है। न्यू मार्केट के रोशन सिंह चौहान, मंजू देवी, बीना देवी, जगदीश लडोला आदि ने बताया कि जल संस्थान के कर्मियों की लापरवाही से पांच दिनों से लगभग 50 उपभोक्ता परेशान हैं। कहा कि कई बार विभाग के अवर अभियंता और फीटर से पेयजल आपूर्ति सुचारु करने की गुहार लगा चुके हैं लेकिन उपभोक्ताओं को विभागीय कर्मियों की ओर से मात्र आश्वासन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा यदि जल्द सिमली न्यू–मार्केट में पेयजल आपूर्ति सुचारु नहीं की गई तो व्यापारियों को दुकानें बंद कर जल संस्थान कार्यालय का घेराव करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

नुक्कड़ नाटक से दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश

जयन्त प्रतिनिधि।

थलीसैंण : राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थलीसैंण की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सात दिवसीय विशेष शिविर के छठवें दिन स्वयं सेवकों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं कन्या भ्रूण हत्या विषय पर जागरूकता रैली निकाली गई।

इस मौके पर स्वयं सेवकों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। साथ ही बेटियों को बेटों के समान शिक्षित करने की अपील की।

राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, हंसेश्वर महादेव से ग्राम बालसिम तक जागरूकता निकाली। स्वयं सेवकों ने रैली के दौरान जिस घर में होता है बेटी का सम्मान, वह घर होता है स्वर्ग समान, बेटी को मत समझो भार, ये तो है जीवन का आधार नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया। बौद्धिक सत्र में मुख्य संदर्भदाता भौतिक विज्ञान विभाग प्रभारी डॉ. सुधीर सिंह रावत ने बिग बैंग सिद्धांत को समझाया। कहा कि कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि अनुशासन, समूहकार्य और समाज की जिम्मेदारी भी है। इस मौके पर प्रयोगशाला सहायक धर्मेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आशीष ममगांई, कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विवेक रावत, सहायक प्रभारी डॉ. प्रमिल्ला चौहान, नरेश चन्द्र उपस्थित रहे।

रसोई गैस सिलिंडर के लिए सुबह छह बजे से लाइन लगनी शुरू

नई टिहरी। रसोई गैस सिलिंडर के लिए उपभोक्ताओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। सिलिंडर रिफिल कराने के लिए लंबी लाइन लगने के कारण कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। रसोई गैस का पर्याप्त कोटा मिलने के दावे के बावजूद लोग खाली सिलिंडर लेकर सुबह छह बजे से ही बौराड़ी बस अड्डे पर लाइन लगाने को मजबूर हैं। रसोई गैस के लिए लोगों को अब भी खूब पसीना बहाना पड़ रहा है।

सुबह छह बजे से दोपहर करीब 12 बजे सिलिंडर समाप्त होने तक लोग लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं। जिले को रसोई गैस का पर्याप्त कोटा मिलने के दावा करते हुए पूर्ति विभाग ने पहले की तरह ही मोहल्ले में ही रसोई गैस उपलब्ध कराने का दावा किया था लेकिन घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी कई लोगों को खाली हाथ लौटने को मजबूर होना पड़ा।

हालांकि यहां जिला मुख्यालय में दो दिन बाद सप्लाई पहुंची। जिससे शनिवार को लोग सिलिंडर रिफिल कराने सुबह छह बजे से ही बौराड़ी बस अड्डे पहुंचने शुरू हो गए थे। रसोई गैस सिलिंडर लेने के लिए लाइन में खड़े यशपाल रावत ने बताया कि वे सी ब्लॉक नई टिहरी से सुबह छह बजे बस अड्डे पहुंच कर लाइन में खड़े हो गए हैं। उसके बाद 10 बजे से वितरण शुरू हुआ तो साढ़े 10 बजे सिलिंडर मिल पाया।

तीन ब्लॉकों के 34 छात्र–छात्राओं को दिए टैबलेट

चमोली। पोखरी, गैरसैंण और कर्णप्रयाग विकासखंड के 34 मेधावी छात्र–छात्राओं को टैबलेट देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान बच्चों को टैबलेट से ऑनलाइन क्लासेस लेकर कॅरिअर बनाने की सलाह दी गई। विकासखंड सभागार में ईशा फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी विनोद सिंह मटूड़ा ने कहा कि बच्चों को लक्ष्य तय कर फिर उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ईशा फाउंडेशन के उत्तराखंड निदेशक भूपेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश स्तर पर 500 छात्र–छात्राओं को चयनित किया गया है। छात्रों को पढ़ाई में बाधा न हो इसके लिए फाउंडेशन की ओर से दिए जाने वाले टैबलेट में पढ़ाई के ही ऐप हैं।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा

जयन्त प्रतिनिधि। चमोली : पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, गोपेश्वर में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक जिलाधिकारी / समिति के अध्यक्ष गौरव कुमार की अध्यक्षता में सकारात्मक एवं सार्थक वातावरण में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ केंद्रीय विद्यालय की प्रधानाचार्य पुष्पलता आर्या द्वारा जिलाधिकारी का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया।

प्रधानाचार्य ने समिति के समक्ष प्रमुख बिंदुओं एवं उन पर हुई प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने विद्यालय के शैक्षणिक सत्र के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रयासों तथा विद्यालय के समग्र विकास से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। बैठक के दौरान विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, संविदा शिक्षकों की भर्ती, शैक्षणिक संसाधनों के सुदृढ़ीकरण तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई। प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत जानकारी में विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन, नवाचार एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में निरंतर प्रगति पर विशेष बल दिया गया। समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी गौरव कुमार ने विद्यालय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत बनाने, आधुनिक सुविधाओं के विस्तार तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए। बैठक के उपरांत जिलाधिकारी ने विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक आनंद सिंह भाकुनी, एसीएमओ वैभव कृष्ण, रिटायर्ड प्रिंसिपल सुरेश चंद्र वर्मा, राहुल राय, प्रधानाचार्य कर्मवीर सिंह सहित विद्यालय प्रबंधन समिति के अन्य सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अवस्थापना विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को प्रदान की वित्तीय स्वीकृति

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में बुनियादी ढांचे एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं उद्यमों को प्रोत्साहन, प्रशासनिक सुदृढीकरण को बढ़ावा देने के साथ ही गंगा कॉरिडोर परियोजना एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं के सुदृढीकरण आदि के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार के इन निर्णयों से राज्य में विकास, निवेश, पर्यटन, ऊर्जा, खेल एवं प्रशासनिक पारदर्शिता को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को इनका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 150 करोड़ तथा विभिन्न विभागों के अधीन संचालित मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु 350 करोड़, की स्वीकृतियों का कायीत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है, इससे राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्यों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत त्रिवेणी घाट के पुनर्विकास हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित 106.78 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इसी विशेष सहायता योजना के तहत वर्ष 2025-26 में प्रथम चरण हेतु अतिरिक्त आंवटन के रूप में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त 11.37 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया। इस परियोजना से ऋषिकेश में गंगा तट का सौंदर्यीकरण होने के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं में वृद्धि तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के तहत जिला एवं राज्य स्तर पर स्वीकृत 22.82 करोड़ के लंबित दावों की देयताओं के भुगतान हेतु 20 करोड़ के पुनर्विनियोग के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इससे उद्यमियों को वित्तीय सहायता एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के उप निबंधक कार्यालयों की अभिलेखों की सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद स्तर पर नीवनीकृत किये जा रहे उपनिबंधक कार्यालयों एवं निर्माणाधीन केन्द्रीय अभिलेखागारों में 24.7 सीसीटीवी सर्विलांस, सेंट्रल मॉनिटरिंग एवं ऑथराइज्ड एक्सेस सिस्टम स्थापित करने हेतु उपनिबंधक कार्यालयों देहरादून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार तथा देहरादून मुख्यालय हेतु 3.95 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

एकजुटता के साथ होंगे प्रयास को बचे रहेंगे जंगलः डीएफओ

चमोली। वन पंचायत परामर्श दात्री संगठन की बैठक में जंगलों को आग बचाने पर चर्चा की गई। इस दौरान महिला मंगल दलों ने वनों को बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम में बदरीनाथ के डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे ने कहा कि आपसी सहयोग से ही जंगलों को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांवों में कई बार खेती बाड़ी के काम में लापरवाही होने से जलते आड़ों से आग जंगलों तक पहुंच जाती है। वहीं शरारती तत्व भी जंगलों में आग लगाते हैं। ऐसे में यदि ग्रामीण, महिला मंगल और युवक मंगल दल, ग्राम प्रहरी, सहित वन विभाग आपसी सहयोग से काम करें तो जंगल आग से बच सकते हैं। संगठन के जिलाध्यक्ष कैलाश खंडूड़ी ने कहा कि वन पंचायतों को मजबूत किया जाना चाहिए साथ ही वनाग्नि के लिए सरपंचों को प्रशिक्षण और संसाधन मुहैया किए जाने चाहिए। आग बुझाते वक्त घायल होने पर मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए। कार्यक्रम में सोनला, बेडाणू आदि गांवों की महिलाओं ने ना काटा तों डाल्यूं....सहित कई पर्यावरण संरक्षण के गीत और नृत्य की प्रस्तुतियां दीं।

इस अवसर पर नंदादेवी के डीएफओ अभिमन्यु सिंह, नंदप्रयाग के रेंजर हेमंत बिष्ट, नागनाथ पोखरी के बीएल शाह, धनपुर के एनके नेगी, लोहवा के प्रदीप गौड़, थराली के मनोज देवराड़ी, नारायणबगड़ के अभिषेक भट्ट, आटागाड़ के आरएके निराला आदि शामिल थे।

जयन्त
संस्थापक
स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी
नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित
–सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469/79
फोन/फैक्स 01382–222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail:
nagendra.uniyal@gmail.com